Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 22, there is one Amendment (No. 37) by Prof. M.V. Rajeev Gowda. Are you moving the Amendment?

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: No, Sir.

Clause 22 was added to the Bill. Clause 23 was added to the Bill.

# CLAUSE 1, THE ENACTING FORMULA AND THE TITLE WERE ADDED TO THE BILL.

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the Motion was adopted.

## The Chit Funds (Amendment) Bill, 2019

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, the Chit Fund Act, 1982 was enacted to provide for regulation of chit funds which have conventionally satisfied the financial needs of the low income households. इस पर ज्यादा जानकारी के बजाय मैं इसे संक्षेप में रखना चाहूंगा तािक आप इस पर विस्तार में बोल पाएं। जब 1982 में यह एक्ट बना था तो उसके बाद लम्बे समय तक एक मांग थी कि जो low income households हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनके पास बचत का कोई माध्यम नहीं था, जिसके माध्यम से उन्हें facility मिल सके। हालांकि कई बार धारणा यह भी रहती है कि कुछ लोग इसे unregulated deposit या Ponzi Schemes के साथ जोड़कर देखते हैं। मैं सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि चिट फंड registration के माध्यम से लीगल है और दोनों में एक अंतर है। जो regulated है, वहां पर deposits लिए जाते हैं और चिट फंड subscription based है, जिसमें समय-समय पर आपको एक निर्धारित धनराशि वहां पर देनी पड़ती है और चिट के माध्यम से आप इसका पैसा भी ले सकते हैं। Nine regulators के बाहर जिनका regulation नहीं था, उन्हें unregulated deposit में गिना जाता था, जिसे Ponzi Scheme कहते थे। सर, जब लोक सभा में चर्चा हुई तब कुछ लोगों ने इसे mix-up किया, इसलिए मैं यह बात सबके ध्यान में लाना चाहता था।

सर, कूल मिलाकर अगर आप देखें, तो इसमें पहले जो लिमिट थी, वह individuals के लिए एक लाख रुपये थी, जिसको तीन लाख रुपये किया गया और फर्म्स के लिए छ: लाख रुपये थी, जिसको बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि 2001 से इसको inflation के साथ लिंक करके देखा गया और उसके हिसाब से इसे तीन गूना बढ़ा दिया गया। जो foreman इस सबको चलाता है, उसकी कमिशन को भी 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर दिया गया, क्योंकि वर्षों से उसका किमशन बढ़ा नहीं था। Compliance को भी पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा चिट निकालने के समय कई बार लोग उपस्थित नहीं होते थे, तो उसमें यह प्रावाधान किया गया है कि video-conference के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। जो video-conference से जुड़ेंगे, फोरमैन की जिम्मेदारी होगी कि दो दिन के बाद वह उनसे रजिस्टर पर साइन करवाए, तािक इसमें पारदर्शिता बनी रह सके और जवाबदेही भी तय हो सके। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चिट फंड का नाम खराब हुआ है, इसके कई उदाहरण हम सबके सामने आए हैं, इसलिए इसकी छवि को बदलने के लिए, इसमें दो नये नामों का सुझाव भी दिया गया, जो 'Fraternity Funds' और 'Rotating Savings and Credit Institutions' हैं। अब इन नये नामों से भी इसको जाना जा सकता है। इसके अलावा डिविडेंड के लिए पहले यह धारणा थी dividend distribution ज्यादातर Companies Act में किया जाता है, लेकिन अब इसको share of discount कहा गया है, ताकि इसे अब पूरानी धारणा के साथ जोड़ कर न देखा जाए। इससे जो पैसा बचेगा, उसको वितरित कर दिया जाएगा।

सर, इसमें जो एक टर्म यूज़ की जाती थी - chit amount, उसको gross chit amount के साथ रिप्लेस कर दिया गया है जो price amount था, उसको अब net chit amount कहा गया है। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा confusion रहता था, इसलिए इसको और अधिक पारदर्शी एवं user firendly बनाया गया है, complince को कम किया गया और अब हम इसको, जो छोटे निवेशक हैं, उसके हितों में लेकर आए हैं।

(उपसभाध्यक्ष, डा. सत्यनारायण जटिया पीटासीन हुए)

[Shri Anurag Singh Thakur]

मुझे पूर्ण विश्वास हे कि जब भी सदन में कोई बिल गरीब लोगों के हितों में लाया जाता है, चाहे लोक सभा में लाया जाए या राज्य सभा में लाया जाए, तो मैंने दोनों ही सदनों में दखा है, इनमें पूर्ण सहमित रहती है। उदाहरण के लिए जब unregulatory deposit पर बिल लाया गया था, तब दोनों सदनों में इस पर पूर्ण सहमित बनी थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बिल पर भी सकारात्मक चर्चा होगी और सबके सहयोग से, जो छोटे निवेशक हैं, उनके हित में हम इस बिल को पास करा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सबाको धन्यवाद देता हूं।

# The question was proposed.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I belong to West Bengal and my State was severely affected by chit fund. I understand what the hon. Minister has said that ponzi schemes and chit funds are not the same. I understand these things but the poor people and the lower middle class people do not take chit funds and ponzi schemes as separate. They think that both are same. My submission would be like this. In my State, I have got the information and we had the experience of seeing this thing and also in other States like Odisha, Maharashtra and Assam where hundreds of thousands of people were severely affected. So many people had died. Common people, those who are poorest of the poor, were cheated. They committed suicide since they did not get the money. Sir, one of our friends went to the Supreme Court. He filed a case. The Supreme Court ordered for investigation and, as a result, investigation started. Still, it is going on. Some political people were arrested. I am not abusing anybody but some political people were arrested. Some non-political people were also arrested. It has been found very clearly that the ordinary people were cheated like anything. Unfortunately, only the State Government wanted to give them some amount but that was most insufficient, but the Government of India did not come out with a single paisa to help these poor people. As a result, still, they are waiting without knowing when they would be getting their money. That is the most unfortunate thing that I have observed in my State and other States too.

Now, the question is this. In this Chit Fund (Amendment) Bill, the hon. Minister has correctly said and I have no intention to say that he is not serious to settle this issue but there is this para 4 in the Statement of Object and Reasons. It says: The Chit Funds (Amendment) Bill, 2018 was introduced in Lok Sabha on 12th March, 2018. The Bill was referred to the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Finance on 27th April, 2018 for examination and report.' Then, what did the Committee say? What had exactly the Committee said, that has not been mentioned here. We do not

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जिटया): मैं मानननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य, डा. नरेन्द्र जाधव जी, बाहर जाना चाहते हैं और उनका समय केवल दो मिनट का ही है, यदि हाउस की इजाज़त हो, तो इन्हें बोलने दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, अनुमति है।

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill subject to certain caveats. The current Chit Funds (Amendment) Bill, 2019 is a welcome addition because it seeks to introduce some changes, which have been long overdue.

In particular, I would like to highlight two provisions which are very welcome. First is, periodically increasing the limits within the Act which is necessary to make the chit fund less restrictive and rigid.

The second provision which is very welcome is the presence of subscribers at the time of drawing the chits, is now allowed through video conferencing. This will certainly make the process more convenient and accessible to subscribers.

Sir, at the same time, I have some reservations about some penalty provisions. First, currently, the punishment for various contraventions, including non-registration of Chit Funds with the State Government, is only up to two years of imprisonment and five thousand rupees as fine. Getting sanction of the State Governments to operate such a Fund is necessary because without the oversight, the likelihood of fraud is extremely high. Escaping from such a critical contravention by payment of just five thousand rupees, as a fine, is severely inadequate.

The second provision which I would like to recommend is that there is an imperative need for a provision in the Bill for punishment and penalty for those individuals and companies which operate with the fraudulent intention to dupe people into believing that they are investing in the chit funds. Most of the pyramid schemes which have been unearthed in the recent past were chit funds in the beginning, to lure in the gullible investors and, later on, they become ponzi schemes.

With these caveats, I strongly support the Bill.

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 का मुख्य उद्देश्य चिट फंड के बारे में समाज में जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करना, इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और इससे जुड़े जो गरीब लोग हैं, जो इसमें सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको न्याय दिलाना तथा उनके हितों की रक्षा करना है। मान्यवर, जब से मैंने होश संभाला है, तब से चिट फंड कंपनियों ने देश में इस तरह का वातावरण बनाया कि चिट फंड कंपनियां, चीटिंग कंपनियों के रूप में जानी जाने लगी थीं। सरकार ने इसमें इसका nomenclature चेंज करने का तय किया है, यह एक वाजिब कदम है, जिससे कम से कम पोंज़ी स्कीम्स, प्राइज मनी वाली

स्कीम्स और चिट फंड्स में differentiation हो सके और लोगों को इनका अंतर पता लग सके। चिट फंड्स कायदे से चलने वाली समितियां हैं और ये वैध हैं। पोंज़ी स्कीम्स को सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है, इसलिए इस अंतर को समझने की जरूरत है, क्योंकि चिट फंड्स सही मायने में छोटे व्यापारी, वर्किंग क्लास और गरीब लोगों के लिए सेविंग्स का भी माध्यम है और आवश्यकता पड़ने पर उनको बगैर बहुत कागजी लेनदेन के शॉर्ट टर्म कैपिटल मिल सके, इसका भी एक बड़ा माध्यम है। हालांकि देश में चिट फंड और पोंज़ी स्कीम्स इसलिए प्रचलित हुई थीं, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं थे। अब इस देश का सीभाग्य, हम सबका सीभाग्य है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा financial inclusion हुआ है,इसके कारण 36 करोड़ से ज्यादा लोग जन-धन खाते से जुड़े हैं। यह एक period में दुनिया का सबसे बड़ा financial inclusion है। Financial inclusion के कारण 80 प्रतिशत लोग बैंकों से जुड़ गए हैं। करीब-करीब साढ़े चार करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला, ग्रीन लोन मिला, वैसे तो साढ़े तेरह करोड़ लोगों को मिला है, लेकिन साढ़े चार करोड़ लोगों को ग्रीन लोन मिला। उन मुद्रा लोन्स से लोगों को जो राहत मिली है, उसको employment के point of view से और बैंक से जुड़ने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बावजूद भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो लोन लेने और सेविंग्स में कागजी लेनदेन में पीछे रह जाता है, उसके लिए यह चिट फंड एक तरह से सहायक सिद्ध होता है। यह बैंकिंग का फेल्योर नहीं है, बिल्क यह बैंकिंग सिस्टम को और बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस विधेयक के माध्यम से इसमें जो संशोधन किया गया है, इसके कारण से चिट फंड रेग्युलेटेड चलेंगे, administratively चलेंगे और जो लोग इसमें घपला करेंगे, उनके लिए इसमें पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है।

सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान्यवर, 1982 से यह विधेयक है और उसके बाद समय-समय पर ..... जब पीयरलेस चलती थी, बहुत लोगों को ध्यान में होगा कि तब पीयरलेस को बचाने के लिए तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारों ने किस प्रकार से घपलेबाजी की और उसको बचाने की कोशिश की। चिट फंड की कंपनियों में पीयरलेस अब तक का सबसे बड़ा स्कैम रहा है, लेकिन उसके बाद किन्हीं न किन्हीं कारणों से चिट फंड कंपनियों में तमाम तरह के घोटाले हुए और इनमें सरकारों की मंशा गरीबों के पैसे को बचाने की न रह कर चिट फंड कंपनियों के माध्यम से घोटाला करने वाले घोटालेबाजों को बचाने की रही है। सब जानते हैं कि अभी चिट फंड कंपनियों में किस प्रकार से घोटाले हुए हैं। शारदा समूह की कंपनियां, इन्होंने करीब-करीब 40 हजार करोड़ रुपए के घोटाले किए। अभी यह अनुमानित है, अभी यह निश्चित नहीं है। Rose Valley Group का घोटाला, MPS Group का घोटाला, iCore का घोटाला, Prayag का घोटाला, Vibgyor का घोटाला और ओडिशा में Safex India Private Ltd. का घोटाला.....

मान्यवर, त्रिपुरा में कुल 37 लाख लोग हैं और 16 लाख लोग चिट फंड कंपनियों के माध्यम से चीटेड हुए हैं। वे ऐसी कंपनियों के द्वारा चीटेड हुए हैं, जिन्होंने भ्रांति फैला कर 16 लाख ाडा. अनिल जैना

लोगों को इससे जोड़ा। इस प्रकार से 16 लाख लोगों को इससे नुकसान हुआ है। त्रिपुरा का कुल बजट 6 हजार करोड़ रुपए का है और वहां पर करीब-करीब 10 हजार करोड़ रुपए की लूट हुई। इन घोटालों में घोटाला करने वाले को पकड़ने के लिए सरकारों को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। शारदा चिट फंड घोटाले में अब तक करीब-करीब सी लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें सब्सक्राइबर्स, डिपॉजिटर्स एंड एजेंट फोरम का दावा है कि 265 लोगों की मीत हो चुकी है। ऐसे घोटालेबाज लोगों को बचाने का काम कहीं न कहीं सरकारों ने किया है। जिन सरकारों ने इस चिट फंड के पैसे को नेताओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, टिकट लाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए किया, उन्होंने गरीबों के पैसों की लूट की है। मान्यवर, यह संशोधन विधेयक लाकर इस सरकार ने गरीबों के पैसे को बचाने का काम किया है। संशोधन विधेयक पर पिछली सरकार में भी एक्पर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया था। एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स ने अपनी रिकमंडेशंस वर्ष 2015 में दीं। वर्ष 2015 में इस मामले को तब की फाइनेंशियल स्टैंडिंग किमटी में ले जाया गया और उसने अपनी रिकमंडेशंस दी। मार्च, 2019 में उस समय के वित्त राज्य मंत्री. श्री शिव प्रताप शुक्ल जी इस विषय को लाए। उसके बाद अप्रैल में यह फिर स्टेंडिंग कमिटी के पास गया और अगस्त, 2018 में स्टैंडिंग किमटी की रिकमंडेशंस आईं। उस स्टैंडिंग किमटी की रिकमंडेशंस को शामिल करते हुए बिल लाने वाले थे, मगर तब तक 16th लोक सभा समाप्त हो गई। अब हमारे मित्र, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी कुछ संशोधन के साथ लोक सभा में इस बिल को लेकर आए। जिस प्रकार से चिट फंड कंपनीज़ के घोटालों से देश के गरीबों के करीब-करीब तीन लाख करोड़ रुपए डूबे हैं और करीब-करीब 15 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए इसे लाने की आवश्यकता अधिक है और ज्यादा प्रासंगिक है। चिट फंड के द्वारा लोगों को इस प्रकार के स्कैम्स से बचाने के लिए और स्कैम्स से गरीबों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्रकार की स्कीम लाई गई है।

मान्यवर, इस स्कीम में नाम बदलने का भी काम किया है। इस फंड को fraternity bond or rotating savings and credit institution बनाया गया है, जिससे इस फंड को थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने भी इस विषय को लोक सभा में रखा था। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों में maximum aggregate amount की लिमिट में बदलाव किया गया है। जो चिट फंड तीन-चार, उससे कम या किसी individual के द्वारा चलाया जाता है, उनमें तीन लाख की लिमिट की गई है और चार, उससे अधिक या फर्म्स के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स में जो पहले छः लाख का प्रावधान था, उसे 48 लाख किया गया है। वर्ष 2001 के बाद अब यह रिवाइज़ हुआ है। मान्यवर, इसमें foreman के कमीशन को भी रिवाइज़ किया गया है, जिससे foreman comfortable हो सके। Foreman का कमीशन, जो पहले पाँच परसेंट था, उसको सात परसेंट किया गया है। इसमें nomenclature, gross chit amount, share of discount, net chit amount का उल्लेख है। पहले कई बार prize amount वर्ड का यूज़ किया जाता था और

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Sir, I rise to support the Bill. At this juncture, we must admit our inability to address the full complexities of the challenges that face us. As a result, half-measured efforts are taken, existing laws are partially amended periodically and we are not facing the actual ground situation or reality head on. Piecemeal amendments to the existing law is a reactive approach. It is a kind of gut-reaction to the situation which develops on the ground. So, legislation to tackle deeprooted problems need deeper study and should cover all transactions. Sir, we are legislating for the future and to protect public interest. But we are not really focusing, in this Bill, on rural credit. We all know that there is distress in the farm sector where money-lenders are holding sway for centuries. There is no mention, in this legislation or any other, to weed out money-lenders who lend money to the poor people at high interest rates.

The big question here is: What is to be done about the past? As an Hon. Member said, it is how we act to recover old dues and return dupad people's money. Chit funds

[Shri Manish Gupta]

are common in many States. We all know about the cases that occurred in the States of Odisha, West Bengal, Gujarat and Delhi. There was a Pearl Chit Fund *ghotala* of Rs.49,000 crore. A former constitutional functionary was the legal advisor of that group. The other large *ghotala* was in Gujarat, by the Oscar Chit Fund. Sir, this is still hanging fire as the investigation is not complete.

The reason for the spread of illegal chit fund companies in certain areas of the country is also due to an ineffective regulatory system. So, there is also confusion with regard to organized and unorganized chit funds. The organized sector should also be included in this law and not left to be glossed over.

We are saying that this Bill secures the interests of the 'Foreman', but, it is silent on the security of the subscriber. This is a huge loophole. Section 16 of the Principal Act seeks the presence of two subscribers which can be done through video-conferencing. We all know that even today many rural areas don't have mobile or internet facilities. The chit fund sector is largely 'unorganized'. You need to include this in the Bill.

Under Section 85 of the Principal Act, this law will not be applicable to chit funds or enterprises started before the enactment of the law. This should be effected retrospectively. I request the Minister so that this issue is also included in the law.

Sir, my next point is about the SEBI and RBI. We have seen in the past, the infirmities that are there in the work of the RBI as far as chit funds are concerned, is so far as unsecured deposits are concerned. The RBI does not include 'Subscriptions to chits'. SEBI rules do not specifically mention chit funds. These have been excluded. I would like to draw the attention of the Hon. Minister as a case here to amend the RBI Act and the SEBI Act. Sir, notably Section 87 and Section 88 of the 1982 Act refers specifically to the role of the RBI. Also, Section 47 of the RBI Act empowers the RBI to inspect chit books and records of any chit fund. SEBI, in the past, received many complaints. These matters were also brought to the notice of the RBI, but because of the infirmities in their area of operation, no action was taken. They have now been activated. Sir, the Ministry of Corporate Affairs runs an investors' education programme through their websites. The websites are there for collecting information on such funds and the promotors. But, how many people in rural India can access websites. So, this is a weakness which needs to be corrected. Also, the banning of Unregulated Deposit

Bill provides an option to the Government for amending three laws, the Reserve Bank of India Act, 1934; the SEBI Act, 1992 and the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002. This shows the path forward. There are multiplicity of agencies that are operating and they need to be empowered substantially and transparently so that they can tackle this menace of chit funds.

The West Bengal State Assembly as far back as in 2003 passed a draft Bill for controlling chit funds, but for almost 10-12 years they have been struggling with the Government of India to get it passed, to get Presidential assent. Even in 2013 and 2014 several moves were made, but nothing fructified. Then, only in 2015, the Presidential assent was obtained. So, there has been a delay in the interaction between the Centre and the State. At the initiative of Ms. Mamata Banerjee, the Justice Shyamal Sen (Retd.) Commission was set up and a Special Investigation Team constituted to arrest the wrong-doers in certain chit fund scams. A sum of Rs. 500 crore was budgeted as a corpus fund from which around Rs. 250 crores was paid to investors who had lost their money.

# [THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) in the Chair.]

This had to be stopped as the case was handed over to the CBI for investigation. There is a case here, which I would request the Minister to look into. Sir, this is a deep-rooted and wide-spread problem of people who have lost crores and crores of rupees. The Central Government should consider coming forward with a budgetary allocation and the Fifteenth Finance Commission can allocate additional resources to the States for compensating duped investors.

The banking system in India is very poor and is not people friendly. So, the banking system needs to be extended. For example, there are twelve bank branches per one lakh adults in India. This needs to be improved. Otherwise, we will not be able to wean away and protect the livelihood of those people who constitute mostly poor people like pensioners, employees, workers, small businessmen, shopkeepers and farmers where lives have been destroyed by rogue chit funds. That is why there is a need to have a re-look at this entire matter. Insurance cover should be provided for the chit funds. This should be made mandatory through a proper law. The proposed amendments do not appear to be adequate to protect the less literate and less conscious investors.

Thank you.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

The Chit Funds (Amendment) Bill, 2019, is introduced to amend the Chit Funds Act, 1982. It ensures transparency in chit fund schemes and aims to protect subscribers. It will also facilitate the orderly growth of chit fund sector to remove bottlenecks and enable greater financial access to people. The Bill was referred to the Standing Committee on Finance and the Committee gave its recommendations. And, now, it is brought before the House to give protection to money of economically weaker sections.

Sir, chit funds are popular among low-income families, as they offer both access to funds and options to save. There is a dire need to protect investors' interest. Chit funds play a crucial role in India's rural economy, providing people with easy access to funds and wider investment opportunities.

In the recent past, we have come across several alleged frauds pertaining to chit fund companies as they lured gullible investors to deposit money in their schemes in lieu of abnormally high returns and subsequently closed their business without any announcement, leaving behind the rural poor in lurch. Since 2016, the RBI has received over 5,200 complaints related to chit fund scams.

Sir, injustice to customers is not only from the small-scale chit fund operators but also from the organized financial institutions like chit fund companies and banks. Therefore, both of them should not be treated at par in case of default or cheating.

This Bill also raised the monetary limits for chit funds by three times, thereby the maximum amount of chit fund collected by an individual kept at Rs. 3 lakhs and by the firms which have more than four partners is up to Rs. 18 lakhs. The individual operators should not be subjected to undue regulations. Since most of them are housewives or middle-class men, it may be difficult for them to maintain records as stipulated in the Bill. Sir, better it may be exempted.

The Bill also raises the commission for the person, who is named as foreman to manage the fund, to 7 per cent from the current 5 per cent. It also allows him a right to lien against the credit balance from subscribers. The Bill further proposes to allow the subscribers to join the process of drawing chits through video conferencing. This is in line with the current digital age and, therefore, is welcome

Hon. Minister of State for Finance had stated that there are more than 30,000 registered chit fund companies in the country. But, the unregularised chit funds would be more than 100 times than this number and the money flow in this sector would, certainly, be phenomenal. Perhaps, because of that, the Bill aims to bring more people under the formal sector. This is a welcome decision. But, the Government should consider that the small-scale operators are functioning under harsh economical conditions. Therefore, care should be taken that they are not subjected to undue harassment. Otherwise, they may quit business much to the hardship of the rural people. As a result, this will only aggravate the unemployment problem, especially in semi-urban and rural areas. The Government should come up with more stringent provisions against big players who flyaway with hard-earned money of poor investors.

The poor people who invest in chit fund at a very low maturity amount of Rs. 10,000 to Rs. 50,000 comprising a group of people is all manned by an individual. This amount will be used by them at the time of emergency, say, health problems, urgent family expenses, agricultural use, etc. For all these purposes, there is no present system available with banks to help them on need-basis. That is why they turn to the practice of saving their money through investment in chit funds in order to get a minimum monthly dividend.

Sir, presently, the Government has increased GST on chit fund from 10 per cent to 12 per cent. When we insist on savings, this will only add to the woes of the subscribers. Paying 12 per cent GST is a huge burden on them and, ultimately, there will not be any gain on their part thereby forcing them to close their chit fund business. This goes against the spirit of encouraging savings. Therefore, I would request the hon. Finance Minister to keep the GST for the large-scale operators at 12 per cent and exempt the small-scale operators totally. When these amendments come into force, the Government of Tamil Nadu has to issue notification with regard to prescription of amount of chit.

With these, I support the Bill on behalf of my party. Thank you.

श्री रिव प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, चिट फंड (संशोधन) विधयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए में आपका आभारी हूं। सर, कुछ चीजें बड़ी मज़ेदार हैं। जो देश भयानक पूंजी के संकट से गुज़र रहा है और जिस देश में सरकारों को बाध्य होकर विदेशी संस्थाओं से बड़े पैमाने पर ऋण लेने पड़ रहे हैं, उनकी शर्तों पर अपनी नीतियों से

[श्री रवि प्रकाश वर्मा<u>]</u>

समझौता करना पड़ रहा है, उस देश ने इस बात का विचार ही नहीं किया कि इस देश में एक अपार क्षमता थी, लोगों के पास जो छोटी-छोटी savings थीं, उन savings को channelize करके कुछ बड़े काम किए जा सकते थे। अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्?ता बता रहे थे कि इन चिट फंड कम्पनियों में अब तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की पूंजी नष्ट हो चुकी है, यानी लोगों ने इतने पैसे जमा कराए, लेकिन वे भाग गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। महोदय, तीन लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। अगर आज आप इसका मूल्यांकन करेंगे और इसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई क्या ये 3 लाख करोड़ रुपए हैं या उससे कहीं ज्यादा हैं क्योंकि जो पूंजी का संकट पैदा हुआ है, उसमें आज सभी लोगों को, छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को भी पैसे की जरूरत पड़ने लग गयी है। जो हमारे organised financial institute हैं, वे कहते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते, उनकी सीमाएं हैं। तो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चिट फंड कम्पनियां बन रही हैं और काम कर रही हैं।

महोदय, यह दर्ज है कि लगभग 30 हज़ार कम्पनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन शायद इससे तीन से चार गुणा या उससे भी ज्यादा, जो लोग काम कर रहे हैं, वे रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। जब इस बात का आकलन किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान के लगभग 15 करोड़ से ज्यादा उन लोगों ने, जो निचले, मध्यम या गरीब तबके के लोग हैं, 3 लाख करोड़ रुपए की रकम खोयी है - यह रकम ज्यादा भी हो सकती है - तो इन परिस्थितियों में इन संस्थाओं का जो पंजीकरण होता है, वह issue बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कैसे उनको संभालेंगे? स्थानीय स्तर पर बह्त से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बीसी करके स्थानीय बाज़ारों में चलता है तथा दुकानदारों के बीच में या हमेशा लोगों के बीच में पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं होते - उन्हें थोड़ा बहुत अनुभव होता है, लेकिन वे पढ़े -लिखे नहीं होते, दुकान चलाते हैं, लेकिन पढ़े-लिखे नहीं हैं। उन्हें regulations के बारे में या financial norms के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनकी schooling ही नहीं है। आज इसकी need बन रही है, एक ऐसा क्षेत्र पैदा हो रहा है, जहां लोगों को बड़े पैमाने पर वित्तीय उप-संस्थानों के बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी होनी चाहिए - हर आदमी को होनी चाहिए। महोदय, इस देश में अगले सेंसस तक 85 परसेंट आबादी नीजवानों की हो जाएगी। ज़रा पूछिए, कितने लोग इस बारे में जानते हैं कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर होना है, कहां पर जाना है? तो कोई आदमी, जो tricky है, होशियार है, वह financial schemes चला रहा है और जो recipients हैं, जो उसके subscribers हैं, उन्हें लगता है कि हां, हम यह चांस लेकर देख सकते हैं या स्थानीय स्तर पर उनका विश्वास है, तो वे समझते हैं कि चलो, इससे एक local support system हो जाएगा, वह पैसा business में काम आ जाएगा या कोई emergency होगी, तो काम आ जाएगा। वे इस बात को overlook करते हैं कि जो आदमी promote कर रहा है, वह tricky है, उसके बड़े-बड़े नेताओं से संबंध हैं, इलाके के दादा लोगों से भी उसके संबंध हैं, उसके पास पैसा जाएगा तो उसे उससे वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा

#### 5.00 P.M.

ज़हमत करनी पड़ेगी। यही तो वह जगह है, जहां हमें कानून चाहिए। इसीलिए तो यह कानून आया है। मुझे लगता है कि जो भी लोग स्थानीय स्तर पर यह अरेंजमेंट करते हैं, वहां के हमारे जो बैंकिंग इन्स्टिट्यूशन्स हैं, बैंक हैं या दूसरे फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, कम से कम उनको तो पता रहे कि किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, किसी नगर में, वह कौन आदमी है, जो इस टाइप के कोई फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन चला रहा है। उसको एडवाइज़ करें या जो भी उसके सब्सक्राइबर हैं, मौका निकालकर कम से कम उनको एडवाइज़ करें। स्थानीय स्तर पर कोई तो ऐसी एजेन्सी हो जो यह देखे कि लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकेगी, उसके लीगल प्रोविज़न्स क्या हैं, चाहे डाकखाने वाले करें, चाहे बैंक वाले करें, हालांकि बैंक वाले थोड़ी बहुत हद तक करते हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, कोई तो इसे करे। सर, आज स्थिति यह है कि पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, प्रैशर बढ़ रहा है, आदमी कहां से लाए ...(समय की घंटी)... Just closing, Sir. सर, फाइनेन्शियल लिटरेसी की स्थिति बहुत खराब है। आपको इसमें कहीं न कहीं कोई प्रोविजन निकालना चाहिए। सामान्यत : लोग अपने खर्चे का हिसाब नहीं रखते हैं। पूंजी नष्ट हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का निर्माण खत्म हो चूका है। मेरा यही कहना है कि जो भी लोग इन संस्थाओं को चला रहे हैं, डिपॉज़िटस ले रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी की रेटिंग का कोई सिस्टम बना लीजिएगा। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके इंश्योरेंस का क्या प्रावधान है, इस बात पर गौर कर लीजिएगा। हमारी जो अधिकृत वित्तीय संस्थाएं हैं, अगर उनके माध्यम से ट्रांजेक्शन्स हों, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सुरक्षा की भावना रहेगी। जो लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, उनकी संपत्तियां ज़ब्त होनी चाहिए, जिससे कि रिकवर करके लोगों की पेमेंट की जा सके। जो भी लोग चिट फंड कंपनियां चला रहे हैं, उनकी अपनी साख का डिटरमिनेशन बहुत जरूरी है, जिससे कि जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता रहे कि हम पैसा लगा कहां रहे हैं। धन्यवाद, सर।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, as I rise to speak about this topic, the first thing that comes to my mind which I also heard from the hon. Members is that there is this chit fund, then there is this 'ponzi schemes' and there are something called credit cooperative societies. They perform almost similar functions, and, unfortunately, all three are under different regulations, and there is one, which is not. There is no regulation at all. That is the 'ponzi schemes.' In the provision, in the original Chit Fund Act, I find that Section 47 talks about RBI's powers and duties. Section 73 gives only advisory role. I really don't understand why RBI should not exercise any kind of control over these chit fund companies, particularly, in the light of what has happened in the chit fund or in the NBFC sector as a whole. The word 'may' is there in all the provisions. In the entire provisions of Section 47 and Section 73, it is 'may'. 'RBI may do'; 'RBI may

[Dr. Amar Patnaik]

do'. There is no compulsion for RBI to do even a sample check. In the cooperative sector, there is similar provision. The credit cooperative sectors in many States also have similar provision. I have a feeling that an integrated approach towards this particular business has not been taken by Government and formation of a Committee which is looking at this particular Act only in isolation is not going to help.

Sir, in the chit fund scams that one has talked about, two main issues were there. One, lack of regulatory control; second, investors were gullible. You have to increase — as Ravi Prakash Vermaji said — investors' knowledge. To protect the investors' interest, the first thing is to increase their knowledge. Nowadays you are going out for outreach of loan, loan. To distribute loans at the retail level, the banks are going for an outreach. Similar kind of exercise to educate the investors about this thing is not taking place. With the result, what is happening is that investors invest in this; they don't ask anybody. But, finally, it is the State Government which is asked to settle this crisis from out of Budget provisions which is from people, from the taxpayers' money who were actually not involved in any way in this business. It is actually unfair. Now, at the same time, in Section 8, which talks about capital adequacy of one lakh rupees, I think, there is absolutely no application of mind here because the capital adequacy norms have to be increased if you want to have some semblance of protection of investors' interest. In Section 12, there is a provision for inspection, records. In Clause 24, the appointment of an Auditor has been left completely to the chit fund company. There is absolutely no control over that. You just get certified financial statements from the chit fund company itself and then carry on the business. We know how the certificates are obtained. Talking about Clause 12, how do you regulate? We know of several chit fund companies which have not given any intimation. By the time the police have realized that they have come into play, they have already collected huge amounts of money. It is not possible to inspect them. Unless there is an intimation which is coming from people, you cannot find out if they have already started operating and have started collecting money. So, I think all the changes that have come are welcome, but I think they are very cosmetic. They have not got into the root of the problem. The harmonization and consolidation of regulatory authorities regulating the acceptance of defaulters from public, about which I have spoken, is most important. There is no whistleblower mechanism prescribed. On increasing the insurance for the deposits, the Standing Committee had said, "There should be provision for insurance coverage for the subscribers the cost of which will be borne by the chit fund company. This is a protective measure for the vast number of subscribers." The Committee,

therefore, recommended that the provision may be brought in the Bill incorporating relevance of insurance coverage for the chit subscribers. But we haven't really taken care of this.

So, in essence, I would say that even if it is a credit plus savings scheme, the first thing is, as some of the Members expressed, if you have to distinguish this from a ponzi scheme, you should rename the Bill and try to bring in the regulation mechanism much more stringently in which case the people who are actually going to get the benefit will not be cheated in future. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much, Dr. Patnaik. Shri Ram Nath Thakur.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 209 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष 1982 में जो छोटे-छोटे दुकानदार थे, जो अपनी कमाई से पैसा बचाकर चिट फंड में जमा करते थे, उनके पैसे चिट फंड वालों ने गंवा दिए। वर्ष 1984 में करीब 20 दुकानदार, जो छोटे-छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे भुजिया वाले, कचरी वाले, लड्डू वाले, जो चिट फंड में पैसा जमा करते थे, उनके पैसे का गबन हो गया। आपने इस चिट फंड (संशोधन) विधेयक को लाकर छोटे लोगों और छोटे दुकानदारों के प्रति बह्त दया दिखाई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो 166 केस सीबीआई के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेने का काम करें। पिछले 37 वर्षो में जितने गरीब लोगों का फंड गायब हुआ है या उसका घोटाला किया गया है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नालंदा जिला में 500 लोगों के पीएसी कम्पनी द्वारा, जो 15,000 करोड़ रुपये ले लिए हैं, जिनका उसने गबन किया है, उस मामले में ठोस से ठोस कार्रवाई हो।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था आप बनायें कि गरीब लोगों के पैसे का गबन न हो, गरीब लोगों के पैसे की रक्षा हो और जिन लोगों ने गरीब लोगों के पैसे का गबन किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं,

> "में नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, दो काम में एक तू काम मेरा कर दे, रोशनी तेज़ कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे।"

उपसभापति महोदय, इसी के साथ, में पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill. On behalf of our Party, Telangana Rashtra Samithi, we wholeheartedly support this Bill. But there are some limitations in the sections that they are amending. I wish to bring those sections, through you, to the kind notice of the hon. Minister and this august House. One amendment is related to Section 2(b). Earlier it was the Chit Funds Act. Now, they want to add here the words "fraternity fund, Rotating Savings and Credit Institution". That is there in Sections 11 and 2. If you take the experience of Telangana, so many poor people start savings scheme within the locality, particularly in an area where there may not be any foreman, that is, an elected body. They collect ₹ 100 every month. Whenever money is required, they take the money by signing and providing one guarantor from among the members. So, they take ₹ 30,000 or ₹ 40,000 and pay back the money in 30 or 40 instalments, as the case may be, with one per cent interest. This is more useful where bankers are not going to the common man and it is here that all these people take money this way only. If we include Rotating Savings scheme into the Chit Funds Act, there will be a problem of harassing the people under the Chit Funds Act. Nobody will pay commission of 5 per cent or 7 per cent; nobody will take money and everybody will work on honorarium basis as elected President and Secretaries. Now, everybody works for two or three days and protect the interest of all the members. Sometimes, it crosses one thousand members. Therefore, whatever Sections are mentioned in the Bill should be clarified. Another thing that I would like to bring to the notice of the august House is that earlier the amount was ₹100. Already chit fund companies are running fifty lakh chits, that is, every month draw is conducted for ₹ 50 lakhs and so on. It is a huge amount. At a time, the number of chits in chit funds is not in one area only, but they are spread over so many different areas. They have companies in fifty or sixty places in different parts of the country. Once a small company, they are spread over entire country and have started business in different areas such as insurance, finance, vehicle finance, etc. There is no clarity in the Chit Funds Act as to what they have to do with the money they have collected from the people. They can take away one instalment without distributing to the members; all the chit fund companies take out one chit amount and invest it in some other area of finance. Is there any provision like that in the Bill? It is nowhere mentioned in the Chit Funds Act. But so many chit fund companies are doing the same thing. We have no objection to increase in the commission of 5 per

cent to 7 per cent, but I request that some clarification may be given on Rotating Savings and Credit Institution in Sections 2 and 11.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I don't think that cosmetic changes in the Act in the form of some amendments can resolve the issue that needs to be addressed today. Why am I saying so? It is because of a large number of chit fund scams that are happening in our country. What are all the amendments? The Act specified various names to refer to chit fund and two more names have been added and also certain terms in the Act have been changed. For example, subscribers are allowed to be present during the time of draw through video conferencing; foreman's commission has been increased from 5 per cent to 7 per cent and the aggregate amount of the chit has also been increased. These are all the amendments. We are doing some cosmetic changes and saying that we are doing something big to address the real issue. Sir, if the Government is serious, I am requesting the hon. Minister to ensure a deposit insurance scheme to protect the subscribers, the customers. It should be made mandatory for all the private companies. As we all know, three types of chit entities are there in our country. One is basically run by various State Governments or maybe by some cooperative institutions etc. The second one is the registered private chit companies. And, the third one is unregulated chit entities mainly closed group associations. So far as the registered private chit companies are concerned, I am asking the hon. Minister, if a company is bankrupt and if it is filing for bankruptcy, what will happen to the subscribers? Whether the RBI or the Government will pay back the subscription that they had already deposited? There is no provision for protecting the subscribers. I am requesting the Government to bring an amendment in the Act to ensure deposit insurance for the subscribers of the chit fund. I think that is very important. Secondly, what about online chits? Nowadays, online chits are very, very common and very, very popular. They are allowed to conduct online auctions. Subscribers are allowed to pay monthly dues online and they can receive thrice the amount online. There is no mention of online chits. It is already there. You are talking about video conferencing but, at the same time, there is no mention of online chits. That is also a very important issue. Thirdly, non-transparency is also an issue. Non-transparency in regard to transaction also has to be addressed. Yes, Sir, we had enacted a legislation to ban unregulated deposit schemes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much.

SHRI K.K. RAGESH: One minute, Sir. Why are instances of chit fund scams rising? We have witnessed Saradha Chit Fund Scam, Rose Valley Scam and even an ex-Chief Minister of State, ex-Chief Minister's son and an ex-MP of a State are also named in a chit fund scam. Sir, why big, big politicians are involved? Why are people being subjected to such kind of frauds? The basic issue is the financial illiteracy. When these companies are promising with huge returns on deposit, poor people become the victims of such fraud. So, I think, it is extremely important to ensure financial literacy and there should be a scheme on financial literacy also. Yes, of course, it is a popular type of saving institution in our country. It provides access to poor people for savings. Because of the limited access to banks, it is really very difficult for the poor people to access the banks. Hence it is, of course, a very important instrument for economy. That has to be protected. But, I am requesting the Government to bring out certain amendments to enrich the Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes, you made your points.

SHRI K.K. RAGESH: Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much, Mr. Ragesh. Now, Mr. Wilson.

SHRI P. WILSON: Thank you, Mr. Vice-Chairman, for allowing me to speak on this Bill. The DMK party had suggested certain modifications in the Bill. The Bill does cosmetic changes and is a window dressing, and does not address the real problems in the chit fund transactions. The chit fund transactions, right from remote village to heart of city, operates as a cash economy and is a parallel economy, which caters to the need of the low income groups and poor people. The Bill is silent as to ^who are the regulators. Is it RBI, CBI, State Government or any other authority? While the principal Act was enacted to regulate chit fund transactions, the Amendment Bill tries to expand the scope of the Act by including fraternity fund, rotating savings and credit institutions. Unfortunately, these new transactions are not defined in the Amendment Bill leading to vagueness in the Bill. The Act indulges in substitutions of terms and redefining 'chits', but does not solve any substantial issues. Now, this Bill does not have a provision for insurance coverage, no safety for the subscribers in case of scams, leaving ultimately the subscribers in lurch. Hon. Finance Minister has to clarify the discrepancies in the Bill. Take the case of Amendment of Section 13. If you compare

the old Act and the proposed Amendment, there are discrepancies. Kindly see Section 13(i). The old Act says, "rupees twenty five thousand", whereas in your Amendment, it says, "rupees one lakh". Which one is correct? Likewise, in Section 13(ii)(a), the old Act mentions the amount as "rupees one lakh", whereas you have shown in your Amendment as "rupees six lakhs". Which one is correct? Is the Amendment Bill wrong? Have the drafters seen what the real Act is? Without noticing, they have introduced this Amendment giving a wrong amount.

### (MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

I would want the hon. Finance Minister to clarify because he himself has enclosed the Act along with this Bill. At page no. 7, I can see the amount that has been described in 13(i) is "twenty five thousand rupees", whereas the Amendment says, "rupees one lakh". Likewise, in 13(ii) also, as I pointed out, the old Act shows "rupees one lakh", whereas the Amendment Bill says it is "rupees six lakhs". Therefore, there are a lot of discrepancies. The hon. Minister has to clarify as to why there are discrepancies. Thank you, Sir.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this very important Bill, which is another step in streamlining the operations of the chit funds in India and protecting the interests of the investors, mainly the economically weaker sections of the society.

Sir, in the recent past, your goodself might have seen the scam in Andhra Pradesh, that is, Agri Gold scam. It had extended to the neighbouring States of Karnataka and Tamil Nadu also. More than thirty-two lakhs of poor and middle-class people were affected because of this scam and they have been duped by the chit fund company. Therefore, I have a bigger reason to support this Bill while giving a few suggestions.

There are some of the positive aspects in this Bill. This Bill addresses not only the need to reforms felt by the stakeholders, the Bill also tries to address the regulatory burden and brings measures to protect the interests of the subscribers. The Amendments have been proposed to facilitate orderly growth of the chit funds to remove the bottlenecks and enable greater financial access to the financially weaker sections of the society as per the Bill. The Bill substitutes the words 'chit amount', 'dividend', 'prize amount' and various definitions have been given. This makes it clearer for the people to understand the chit fund schemes as well as it will be easier for the court to prosecute the offenders. This Bill also enables greater control of the respective State Governments on these funds.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Sir, I have a few suggestions to be made to the hon. Minister. First, a system of paying back the cheated depositors should be institutionalized. In fact, as I have told just now, in the recent past, in the Agri Gold scam, where 32 lakh depositors have been cheated, the Government of Andhra Pradesh and the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Jaganmohan Reddy garu, has given back the deposits from the State Exchequer to the extent of Rs.10,000 for each of the depositors. Therefore, in case of cheating by these companies, a mechanism can be worked out which can be institutionalized where the depositors will not be put to loss. Sir, the chit funds are needed because of the lack of financial inclusion of the rural and semi-urban people. Therefore, I support the Bill. The Government should further take steps towards the financial inclusion of the poor and those in need of emergency money. The last suggestion which I would like to make in this regard is that the chit funds give both lending and saving facilities to those under served by financial institutions. Therefore, I urge the Finance Ministry to ensure that the financial institutions are accessible everywhere and for everyone. Thank you very much.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, मैं चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इसका इतिहास ठीक नहीं रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, किन्तु माननीय मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से कानून में काफी परिवर्तन किये हैं और यह बिल लेकर आये हैं, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, चिट फंड अधिनियम, 1982 को चिट फंडों के विनियमन का उपबंध करने के लिए लाया गया था और प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य चिट फंड क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास करना और इस उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करना है।

चिट फंड वर्षों से छोटे कारोबारों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति लॉटरी द्वारा, नीलामी द्वारा या अन्य किसी रीति में अथवा अपनी बारी आने पर संग्रहित राशि प्राप्त करता है। इस प्रकार, वे व्यक्ति, जिनको निधियों की आवश्यकता है और बचत करना चाहते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं की पारम्परिक रूप से पूर्ति करने में समर्थ होते हैं।

महोदय, विधेयक के खंड 2 और 11 द्वारा चिट फंड की सूची में दूसरे नाम भी सुझाये गये हैं, जिससे इसकी नकारात्मक छवि सुधरेगी और चिट फंड वैध कारोबार के रूप में स्थापित हो सकेगा। विधेयक के खंड 13 में व्यक्तियों की संकलित चिट राशि की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 3 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकारों को चिट की सीमा निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है, जोकि एक प्रशंसनीय कदम है।

इससे छोटे निवेशकर्ताओं में ऐसी किन्हीं स्कीमों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उन्हें इनके जिएए धन जुटाने में आसानी होगी। चिट फंड के मुखिया का कमीशन भी 5 से बढ़ा कर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव है, जिससे वे छोटे निवेशक की बकाया रकम को एडजस्ट कर सकेंगे और चिट से पूँजी निकाल चुके अंशधारकों को असंबद्ध किया जा सकेगा। इससे स्कीम के डिफॉल्टर होने और पूंजी डूबने का खतरा कम होगा।

पोंजी स्कीमों पर पहले भी सरकार कानून लेकर आयी है, परन्तु देश भर में चिट फंडों द्वारा लोगों के ठगे जाने का काम बहुत समय से चल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में लोग ठगी के जाल में फंसे हैं और सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या भी की है। एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 2 करोड़ छोटे निवेशकों का करीब 4 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में 194 कम्पनियों के खिलाफ जाँच चल रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ऊँचे रिटर्न का सब्ज़बाग दिखा कर लोगों का पैसा ठग लिया और नियम-कानून की धिज्जियाँ उड़ाते हुए निवेशकों को 60,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया। इसमें जनता का पैसा जमा करने वाली कई फर्जी कम्पनियों पर सीबीआई ने धावा बोला है, जिनमें बहुत से गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों ने अपना पैसा गँवा दिया। मेरा मानना है कि चिट फंडों और जमा योजनाओं की निगरानी, लेखा परीक्षण और नियमन ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ केन्द्र सरकार और स्वतंत्र अधिकरण हमेशा ही निवेशकों के मामले में नाकाम होते आये हैं, जिससे चिट फंड योजनाएँ नियमन की खामियों का दुरुपयोग करती हैं।

महोदय, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वह अवैध और फर्जी योजनाओं से निबटने के लिए अनुपालन और जागरूकता को बेहतर बनाये। वित्तीय फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो और वित्तीय योजनाओं के मामले में नियमन के लिए एक एकीकृत नियामक संस्था स्थापित की जाए, जिससे कानून के अनुपालन में मदद मिलेगी। घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जनता को शिक्षित एवं जागरूक करने की जरूरत है, ताकि उसे वैध और फर्जी स्कीमों का अन्तर समझ में आ सके और बड़े-बड़े वादों के मामले में वह सावधानी बरत सके। मैं चाहूँगा कि वह अंशधारकों के लिए बीमा कवरेज को शामिल करे। इससे पूँजी के साथ गरीबों के जीवन की भी सुरक्षा हो सकेगी और उनका फंसा धन वापस हो सकेगा।

महोदय, मैं कुछ और सुझाव देना चाहूँगा। जैसे, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए जो चिट फंड कम्पनियाँ बनती हैं, उनका रिजस्ट्रेशन करते समय यह देखा जाए कि उनके पास उतनी सम्पत्ति है या नहीं है, तािक उनके गायब होने के बाद कम से कम उससे वसूला जा सके। दूसरा, इस तरह की कंपनियां बनती हैं, ऑफिस खुलता है और लोगों से पैसा ले लिया जाता है। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो रातों-रात ऑफिस गायब हो जाता है और कर्मचारी गायब हो जाते हैं। मेरी यह मांग है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए।

[श्री वीर सिंह]

महोदय, उत्तर प्रदेश में अमरोहा जनपद है, वहां पर AMTLIFY नामक एक रियल एस्टेट कंपनी आई और उसने वहां पर अपना ऑफिस खोला। वहां लोगों को कहा कि हम आपको पैसा बढ़ा कर देंगे, प्लॉट देंगे और उसने पांच-छ: महीने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद वहां से गायब हो गयी। उसने वहां पर पैसा इकट्ठा करने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए थे, कंपनी तो गायब हो गई, लेकिन अब पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, जो वहां के लोकल लोग कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन है कि इस पर थोड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए तथा इस कानून को और सख्त बनाया जाए, धन्यवाद।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, 30,000-plus registered chit fund companies are dealing in ₹ 40,000 crores. Naturally, the enormity of the unregistered chit fund industry is manifold as compared to the registered one. Sir, in our State, from the late seventies, the chit funds were operating. The Sanchayita scam was the first big scam that came up. In 2013, the present Bengal Government brought the Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act but the Central assent was not given till 2015. The State Government also introduced a scheme for payment compensation and created a corpus of ₹ 5,000 crores. Now, enforcement of a Commission was also rendered. What are the safeguards available for investors? The Minister is here. The insurance companies are not involved in the process. They could, at least, safeguard the interest of depositors who are generally from the marginalised section. The Union Government continues to remain in a state of denial over the fact that the Indian economy has virtually entered into a state of recession. The Government, in two instalments, has announced packages of ₹ 2.15 lakh crore in the form of tax cuts and benefits to the corporates. The huge Non-Performing Assets have piled up because of large-scale defaults by big corporate houses. In last five years, NPAs have risen fourfold, and, loans of, at least, ₹ 5.5 lakh crore have been written off since 2014. In this scenario, people are forced to turn to small investment schemes.

I want to know from the Government as to whether the Government has considered collating data of investors and companies. If so, what is the regulating oversight? The data protection Bill, Sir, has still not been tabled in the Parliament. The question of privacy and surveillance needs to be addressed by the Government.

Lastly, creation of awareness for promotion of financial literacy amongst small investors regarding the pros and cons needs to be effectively implemented. Through you, Sir, I will request the Government to look into this matter. Thank you.

SHRI NARAIN DASS GUPTA (NCT of Delhi): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Chit Funds (Amendment) Bill.

Sir, -I have risen to support this Bill with a few suggestions to the hon. Minister. Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to two technical amendments which need to be incorporated immediately in this Bill.

Sir, sub-Section 2 of Section 1 of the Chit Funds Act, 1982 states that this Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. I think, the words "Jammu and Kashmir" need to be deleted from the original Act. This is first technical amendment. Secondly, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to Section 24 of the original Act of 1982 which mentions about the maintenance of accounts and balance sheet, and, where they have given the reference that it should be audited by the auditor who is eligible under the Companies Act, 1956. Sir, being the Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs, you are aware that now the Companies Act, 1956 does not exist and as such it should be substituted by the Companies Act, 2013. These are the two small amendments to be incorporated in the original Act itself. Apart from this, I would also like to refer to two suggestions. Sir, you have taken a decision to extend the aggregate chit fund from one lakh rupees to three lakh rupees and six lakh rupees to eight lakh rupees. I agree with this. But my suggestion is that it can be left to the discretion of the States because it differs from State to State. You have said that you have increased it because of inflation that has taken place over the years. While referring to it, you have increased the commission from five per cent to seven per cent. I think that does not go with the inflation. If you increase the aggregate amount here, it will automatically take care of the commission of the foreman. If you think so, it can be restricted to five per cent.

Section 2(b) of the Act says that every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead). Why is it restricted to grains? 'Grain' can be replaced with 'certain things in kind'. Why is it restricted only to grains? If you are giving the benefit of subscription in kind, then it should be written here 'certain things in kind'.

I would like to draw your attention to Section 24 where audit is prescribed. It is all right because audit should be done. But as per the provision, it will certify the financial statement. It is a technical subject and a number of compliances are required. Even under the Income Tax Act, there are a number of provisions where separate audit reports are required other than the report on the financial statement. My submission is that here we can mention 'audit be done as per the Companies Act and as per the prescribed format'. Rules will take care of that and that matter can be referred to the Institute of Chartered Accountants. They may come out with a format of the audit, especially for the chit funds. With these suggestions, Sir, I fully support the Bill. Thank you very much, Sir.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I am sure the Government also will join me in admitting that the economy of the country is in deep crisis. Five trillion dollar economy of our dreams will not become a reality soon. Indian rural life is in great despair. In that situation, chit funds are coming to the poor people with a lot of promises. What has happened, Sir? All over the country, we can see chit funds have become cheat funds. They cheat the people. They loot the people. How do they do it? Saradha Chit Funds cheated ₹ 25,000 crore from 1.7 million people. Rose Valley plundered ₹17,520 crore from five million people. Another name is Agri Gold. Nobody knows how many people they have cheated and how many crores they have plundered. The list is so big. I want to read all the names here. All the chit funds are hiding somebody, who are big people of the Government or have political life behind them. Without them, no chit fund can plunder the people. Only with the political support of the big people at the helm of affairs, this has happened. The interest of the poor people has to be protected. But it cannot be done by this kind of cosmetic amendments. The amendments are brought here only for the sake of bringing them. Some names have been changed. Some per cent of commission has been increased. But with that, what can we save? The interest of the poor people cannot be saved by this. Chit funds have to be regulated in the most effective manner for which the Government has to be ready politically and administratively also. The banking system is in a very poor shape. Day by day, banks are closing down rural branches. Coming together of banks has helped whom? Only the rich. The poor are the sufferers. Once upon a time, they looked up to chit funds with great hope that chit funds were for them only. When rich players came to the field, even chit funds became a rescue for the big people and the poor became only a prey to be plundered and looted. That is what is happening here. In this situation, we need basic changes. A small thing but a good thing is that the depositors' savings have to be insured by the Government. In this Bill also, that part is silent. It is a very important part but the Government wants to keep mum on that part. I request the Minister to take it seriously and make a provision to see that the money of the poor men is insured by the Government itself. By RBI or SEBI or by some kind of strong Acts, it can be secured. Otherwise, what you are saying here will bring no results. The poor will remain poor. Their money will be taken away by the rich. I am sure that big people and their political parties are the criminals behind this play. With these words, I conclude.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): माननीय उपसभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बिल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग छोटी-छोटी बचत करते हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिले। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यह बिल लोक सभा में पास हुआ है और आज इसको राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अभी कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है और इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रही है, जबिक अधिकांश सदस्यों ने यह कहा कि यह बिल बहुत बढ़िया है और उन्होंने कुछ सजेंशंस दिए, जो कि अच्छी बात है।

माननीय उपसभापित जी, इसके जो features हैं और इसके जो advantages हैं, उनको बताने से पहले मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार कितनी संवेदनशील है और वह financial matters के अंदर कितनी संवेदनशील है। देश के करोड़ों लोग, जो अपनी छोटी-छोटी या बड़ी बचत करके जिन बैंकों में अपने पैसे डिपॉजिट करते थे, वे financial institutions, चाहे वे पब्लिक हों, प्राइवेट हों या वे non-banking finance से संबंधित हों, उनमें उनके डिपॉजिट्स का end use और लोन के माध्यम से प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल न करके जो मिसयूज़ होता था, उस पर रोक लगाई जा सके। उनके पैसे का मिसयू यह होता था कि कुछ होशियार लोग, जो लोन तो किसी और कारण से लेते थे, लेकिन उसका end use जो होना चाहिए था, वह न करके उसको किन्हीं और सेक्टरों में invest कर देते थे। वे उनके पैसे का investment क्या करते थे, बल्कि मैं यह कहूँ कि उनके पैसे के illegal transactions किए गए।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि financial matters के अंदर, चाहे वह चिट फंड हो, लॉटरी स्कीम्स हों या इनामी स्कीम्स हों, उनके माध्यम से करोड़ों लोगों को ठगा गया और इस तरह से लाखों-करोड़ों रुपये के एमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। उन सबके लिए कहा गया कि जो छोटी बचतें हैं. उनमें लोग किस तरह से ठगे जाते हैं। सर, उसका एक ही कारण था कि देश की बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में सिद्धांत तो यह है कि उससे हमारी बचतों को प्रोत्साहन मिले, छोटी-छोटी बचतों के लिए बैंक में खाते हों और उन खातों में वे सेविंग्स सुरक्षित रहें, परन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि पब्लिक सेक्टर में भी बैंक खोले गए और प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक हुए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में छोटी सेविंग्स करने वाला व्यक्ति, इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति उससे लाभान्वित नहीं होता था। विशेष रूप से, रूरल एरियाज़ तथा सेमी-अर्बन एरियाज़ में छोटी बचत करने वाले लोगों को बहुत सारे प्रलोभन देकर उनकी बचतों को irregular method से collect कर लिया जाता था। उससे बचने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने आते ही यह कहा कि देश के लिए financial inlusion और financial literacy बढ़े, देश के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था का ज्ञान हो और बैंकों में उनके एकाउंटस हों। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहुंगा कि जिस देश में वर्ष 2014 तक 12 करोड़ अकाउन्ट्स खोले गए हों और करोड़ों-करोड़ गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से दूर कर दिया गया हो, उनको राहत देने के लिए 36 करोड़ से भी अधिक लोगों के अकाउन्ट खोले गए। जब अकाउन्ट खोले गए तो बहुत सारी बातें उठीं कि उनके पास पैसा नहीं होगा, ज़ीरो बैलेंस के अकाउन्ट से banking industry को नुकसान होगा, वे कैसे [श्री रामकुमार वर्मा<u>]</u>

74

अकाउन्ट्स मेन्टेन करेंगे? लेकिन हज़ारों करोड़ रुपये की सेविंग्ज़ उन बैंकों में जमा हुई। इस तरह से हमारे छोटे डिपॉज़िटर्स को राहत मिली, उन्होंने अपनी बचत को जमा किया और बैंकिंग व्यवस्था में जब इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो, उनके लिए पैसा मिला, advances भी बढ़े। जन-धन अकाउन्ट के माध्यम से उनको प्रोटेक्ट किया गया। इतना ही नहीं हमारे जितने advances थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जो व्यक्ति लोन लिया करते थे, उसको सही जगह यूज़ न करके प्रॉपर्टी बनाने में यूज़ किया करते थे। बेनामी संपत्ति का आना, भगोड़े कानून को लागू करना, unregulated deposits के लिए लॉ बनाना और में कहूं कि Insolvency and Bankruptcy Act का बनाना केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। यह किमटमेंट है कि जो भी देश के फाइनेंस सिस्टम में बचत करता है, उसको सुरक्षा मिले। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज विट फंट के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं और माननीय सांसदों ने बताया है कि किस तरह से उगी की जा रही है। विभिन्न नामों से लोगों से धन इकट्डा किया जाता है और उनको उग कर, उनकी गाढ़ी कमाई को हज़म कर लिया जाता है।

वर्ष 1982 में तत्कालीन सरकार का प्रयास था कि यह चिट फंड एक्ट के माध्यम से ऐसे उन छोटे बचतकर्ता, जिनके close relationsहोते हैं। चिट फंड का एक criteria, concept यह होता है कि छोटे बचतकर्ता, close relations के लोग, कुछ संख्या के अंदर अपना share subscription करते हुए इकट्ठा करेंगे, वे आपस में अपने norms तय करेंगे, उसे हम बट्टा के रूप में कहें, नीलामी के रूप में कहें या पहले उसको dividend बोला जाता था, उसके रूप में जो need है, उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए no profit, no loss के आधार पर सभी को वे बांट कर अंत में जिसका पैसा बचता था, उसको बांट लिया जाता था। मकसद यह था, लेकिन बीच में जिस तरह के fraud चिट फंट और लॉटरी के नाम से या अन्य ईनामी योजनाओं के नाम से हुए। वर्ष 1982 के अंदर एक्ट बना, लेकिन समय के अनुसार जो एक्ट के प्रावधान थे, वे प्रासंगिक नहीं हुए। उसके लिए वर्ष 2011 में Key Advisory Group की कमेटी ने एक्ज़ामिन किया, उसकी रिपोर्ट आयी, उसके बाद उनकी सिफ़ारिशों को देखते हुए धीरे-धीरे एक्ज़ामिनेशंस हुए और 16वीं लोक सभा के दौरान इस बिल को वर्ष 2018 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा उसकी जांच के लिए उसको पेंडिंग करते हुए कमेटी को भेजा गया। फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी ने जो भी रिकमंडेशंस किए, उनको include करते हुए, पुन: उस पर स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से उस पर examination हुआ। जैसे ही 16वीं लोक सभा के अंत में इसको प्रस्तृत किया जाना था, लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और वह बिल पास नहीं हुआ। पुन: इसके एक्ट के अंदर प्रोविज़ंस में अमेंडमेंट करते हुए लोक सभा ने पास किया और राज्य सभा में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। ...(समय की घंटी)...

श्री रामकुमार वर्मा: सर, अभी समय है।

श्री उपसभापति: 8 मिनट हो गए हैं, पार्टी के अन्य वक्ता भी बाकी हैं।

श्री रामकुमार वर्मा: आप कितना समय देंगे?

श्री उपसभापतिः दूसरी तरफ भी लोग हैं।

श्री रामकुमार वर्माः वे अपना समय कम करेंगे। इस तरह मैं यह कहना चाहुंगा कि आज विभिन्न स्टैंडिंग कमेटीज़ या हमारी Key Advisory Group और विभिन्न कमेटीज़ की recommendations को अच्छी तरह से देखा गया है। इसके अंदर जो सेक्शन में अमेंडमेंट किए गए हैं, उन कमेटीज़ की रिकमंडेशंस को पॉजिटिव लेते हुए और क्लॉज़ 2 के अंदर बहुत सारे नामों से चिट, चिट फंड और कुरी उसमें एडीशनल इंसर्ट करते हुए fraternity fund and rotating savings को उसमें जोड़ा गया है। ये रिकमंडेशंस कमेटीज़ की हैं। इसी तरह क्लॉज़ 2 के साथ gross chit amount, share of discount & net chit amount in place of chit amount, dividend और prize amount किया गया है, जो नाम से भी कुछ ठीक नहीं लगते थे, उसका भी प्रोविज़न इसमें किया गया है। अगर क्लॉज़ 13 को देखें, तो हमारी individuals की जो सीमा थी, वह एक लाख थी और 2001 की महंगाई के आंकड़ों के इंडेक्स को देखते हुए उसमें प्रोविज़न किया गया है, जो justified है और suitable भी है। उसे एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये किया गया है। फार्म्स जो चार व्यक्तियों से अधिक हैं, उनके लिए इसमें 6 लाख की जगह 18 लाख का प्रोविज़न किया गया है। इसी तरह से पहले यह होता था कि जब भी चिट फंड वालों की लॉटरी या चिट फंड का जो ड्रॉ निकलता था, उसमें दो व्यक्तियों की उपस्थिति होना अनिवार्य था उनके उपस्थित नहीं होने पर। यह होता था कि कभी needful व्यक्ति, जो needy है, उसको पैसा नहीं मिलता था। उस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए उसमें प्रोविज़न किया गया है कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दवारा भी उसकी उपस्थिति दर्ज होगी और बाद में उनको मिनटस में verify कर लिया जाएगा, यह भी इसमें किया गया है। इसी तरह से कमिशन का रेट, जो foreman प्रधान के रूप में काम करता था, मैनेजमेंट उसको करने में interested नहीं होता था। उसको मद्देनज़र रखते हुए 5% से 7% तक उसको इंक्रीज़ किया गया। मैं समझता हूं कि पूरे बिल को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें, तो चाहे हमारी स्टैंडिंग कमेटी हो ...(समय की घंटी)... चाहे वह हमारा गुप हो, उसका अध्ययन करते हुए उनको इसके अंदर include अ किया गया है।

सर, मैं समझता हूं कि इसके बाद पूरा सदन भी उसको सहमित से पास करने जा रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में चिट फंड के नाम पर जो इररेगुलेटेड ट्रांज़ेक्शंस होती थी, उन पर रोक लगेगी और उन व्यक्तियों को राहत मिलेगी। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

SHRI GC. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Bill. Sir, chit funds started more than 200 years back, and some of the Chit Funds became Banks, and became part of people's life for their small savings for education, marriages, medical services, purchasing

[Shri G.C. Chandrashekhar]

properties and immediate emergency needs. For all these reasons, Chit Fund business has grown in a big way. As per media reports, the total size of unregistered chit funds is almost ₹ 30 lakh crore which is one year GDP of the country.

Sir, the amount lost in the chit fund scam is not small but it is ₹ 3 lakh crore of the poor people. Even after so many scams and money lost by people; still people are attracted towards Chit Funds due to high return to people, people can withdraw money easily, whenever they want; banking infrastructure still very poor in villages so they find an easy way of saving their hard-earned money; low interest rates given by banks and less documentation required.

Sir, recently the HDFC bank started mentioning in the customer's pass book that they will cover only  $\ref{1}$  lakh insurance, due to this, people became panicky all over the country. If I deposit  $\ref{1}$  lakhs, and something goes wrong in the bank, then, I will be getting only  $\ref{1}$  lakh, and I will not get another  $\ref{1}$  lakhs. This has become very viral. Due to this, people are losing faith in the Banking System. Also, the Government is not allowing to keep the money at their houses, which indirectly attracting towards Chit Funds.

Sir, I would like to bring to your kind notice some of the big scams. Six crore families are cheated by PACL scam of Rs. 50,000 crores. All the affected families are on the road today. There are some more scams like the Saradha Chit Fund Scam estimated around ₹ 21,000 crores and Sahara Chit Fund Scam is of worth ₹ 15,000 crores. Many of these companies get registered, collect the money from the people and runaway by closing the business. Around 15 crore people are affected by Chit Fund Scams.

Recently, in Bengaluru, there are 193 registered chit fund operations under the Chit Funds Act 1982, with a turnover of about ₹ 4,000 crore per annum. The number of unregistered chit fund companies in Bengaluru is around 2,000 with about ₹ 45,000-50,000 crores as annual turnover. Recently, the country has witnessed the IMA scam in Bengaluru, which has cheated more than 40,000 lower income families, which is estimated around ₹ 10,000 crore. Along with this, some of the major Ponzi schemes include the Rose Valley Ponzi scheme, ₹ 15,000 crores; Basil International, ₹ 3,500 crores; Seashore Group of chit scam, ₹ 850 crores. Sir, India has around 15,000 chit fund

companies. Over 80 per cent are family-owned chit fund companies. Ninety per cent of the family-owned chit funds have repeat customers. Sixty per cent of the customers are from rural India. Out of 15,000 chit fund companies, less than one per cent runs it as professional business unit, while the rest work as unorganized setup. Recently, the Parliamentary Standing Committee on Finance had suggested the Government to introduce insurance coverage for safety and security of the money of the subscribers. But there is no such clause in this Bill. It should be included. In the recent days, the people are losing trust on the banking system due to scams, mismanagement and high NPAs. Hence, it is becoming very difficult for the people to avoid investing in chit funds. All the investors should be insured. The majority of the people, who invest in chit funds, are poor people, who invest their money for emergency purposes. Therefore, I strongly propose to take stringent action against defaulters, with a merciless law to prevent such frauds.

### SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the discussion on the Chit Funds (Amendment) Bill, 2019, will continue further. Now, the Special Mentions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kailash Soni; not present. Ch. Sukhram Singh Yadav; not present. Shrimati Chhaya Verma.

# Demand for release of extra funds for Naljal Yojana in naxal-affected areas in Chhattisgarh

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में "नलजल योजना" के तहत बसावटों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि नक्सली क्षेत्रों में बसावटें विरल होने के कारण लागत अधिक आती है, लेकिन भारत सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त लागत वहन नहीं की जाती है, इससे योजना के तहत संचालित "नलजल योजना" का कार्य बाधित होता है। गर्मियों में इस क्षेत्र के जलस्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है। जल की कम उपलब्धता के कारण नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक मेहनत से जल का इंतज़ाम करना पड़ता है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है।

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनंदगांव, महासमुंद, बालौदा, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोण्डागांव में "नलजल